income-tax is allowed to exporters of goods and merchandise under Sec. 80HHC of the Income-tax Act in view of the fact that in commodity export there is low profitability on account of the comparative disadvantage faced by the Indian exporters in the international market. On the other hand in the case of project exports, there is no such disadvantage. In view of the good profitability in project exports, tax concession of 50 per cent only is allowed under Sec. 80HHB, which is considered to be adequate.

Increase in narcotics production in the country

4595. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA : Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the drug manufacturing units in the States of Bihar, U.P. and Madhya Pradesh are producing narcotics and are supplying to addicts even in Bangladesh;

(b) whether it is also a fact that considerable percentage of the heroin seizures in 1990 showed its origin in India and that its production is gradually increasing following the opening of land routes through Afghanistan;

(c) if so, what are the details thereof; and

(d) what measures are contemplated by Government to check the conversion of opium into heroin in the country?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI RAMESHWAR THAKUR) : (a) Five clandestine make-shift laboratories engaged in the manufacture of heroin from opium were unearthed in the State of U.P. during the years 1990 and 1991. No information has been received about such laboratories supplying drugs to addicts in Bangladesh.

(b) and (c) No, Sir.

(d) Enforcement agencies keep a vigil in the matters to check such illegal activities. Vigil is also maintained over the illicit cultivation of opium poppy with a view to prevent diversion of opium into illicit channels. The enforcement agencies concerned collect intelligence about such illegal activities and whenever such illegal activities are noticed, action is taken in accordance with law.

Government decision to borrow Rs. 1208 crores

4596. SHRI SYED SIBTEY RAZI: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether his Ministry has taken a surprise decision to borrow on a dearer basis and secure the balance of Rs. 1208 crores in the final tranche for the current financial year;

(b) if so, what are the reasons behind this change in the pattern and what is the basis of borrowing;

(c) what is its impact on the Statutory Liquidity Ratio; and

(d) whether this scheme has been fully publicised through media to achieve the desired targets?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SHANTA RAM POTDUKHE): (a) and (b) The last instalment of Central Government borrowing, in a year, is usually done in the month of March. This time also the last instalment was borrowed on the 25th of this month. The rate of interest for the 15 year loan which was earlier 11.5% was increased to 12.5% to improve the return to investors.

(c) This has no impact on the Statutory Liquidity Ratio.

(d) Yes, Sir.

मुद्रा स्फीति के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक की टिप्पणी

4597. **डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :**
श्री राम जेठमलानी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 9 मार्च, 1992 के "इकॉनामिक्स टाइम्स" "निगेटिव जी०डी०पी० ग्रोथ रेट, स्पाइरलिंग प्राइसिस इन 1992-93 फोरकास्ट" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सही है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने यह कहा है कि अगले वर्ष के दौरान भी मुद्रास्फीति की दर में कमी आने की कोई संभावना नहीं है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) मुद्रास्फीति की दर जो अगस्त, 1991 के चौथे सप्ताह में 16.7 प्रतिशत के शीर्ष पर पहुंच गई थी, वह गिरकर 7 मार्च, 1992 को समाप्त सप्ताह में 12.6 रह गई थी। सरकार का निश्चय मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का है, इसलिए 1991-92 के दौरान मुद्रास्फीति की दर और अधिक कम हो जाने की आशा है। बृहत्-आर्थिक स्थिरीकरण की प्रक्रिया और आर्थिक सुधार जो वर्तमान वर्ष में आरंभ किए गए हैं, और 1992-93 के बजट प्रस्तावों में जिन्हें सुदृढ़ बनाया गया है, उनसे देश में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता लगभग सामान्य होने और उत्पादन में तीव्र वृद्धि लाने में सहायता मिलेगी जिससे मुद्रास्फीतिकारी दबाव कम हो जाएंगे।

विदेशी कंपनियों द्वारा बाहर भेजी गई विदेशी मुद्रा

4598. **डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :**
श्री रणजीत सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले कुछ वर्षों में देश में विदेशी मुद्रा का बहिर्गमन निरन्तर बढ़ता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत आने वाली कंपनियों ने कितनी विदेशी मुद्रा देश से बाहर भेजी तथा यह धनराशि किन-किन मदों के नाम पर बाहर भेजी गई;

(ग) इन कंपनियों द्वारा उपरोक्त प्रत्येक वर्ष के दौरान देश के उद्योगों में कितनी विदेशी मुद्रा और भारतीय पूंजी निवेश की गई;

(घ) क्या यह भी सच है कि इन कंपनियों के लाभांश भारतीय कंपनियों से अधिक थे; और

(ङ) यदि हां, तो वर्ष 1990-91 में इन कंपनियों के विदेशी पूंजी निवेश के मुकाबले इनका लाभांश कितने प्रतिशत था?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कृषि क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋणों में वृद्धि

4599. **डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :**
श्री राम जेठमलानी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि औसत उत्पादन दर में वृद्धि करने, नई तकनीकों और उपायों का प्रयोग करने तथा बीजों, उर्वरकों इत्यादि के अधिक मूल्यों के कारण भी कृषि क्षेत्र में अधिक पूंजी निवेश किये जाने की आवश्यकता है,

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा प्रति वर्ष मंजूर किए गए कुल ऋण में से कृषि क्षेत्र को औसतन कितने प्रतिशत ऋण दिया गया है; और

(ग) क्या सरकार ने इस प्रतिशतता को बढ़ाने के लिए कोई निर्णय लिया है; और यदि हां, तो कृषि क्षेत्र को ऋण प्रदान करने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) :(क) से (ग) वाणिज्यिक बैंकों के प्राथमिकता क्षेत्र ऋणों के मुख्य घटकों में कृषि भी एक घटक है कृषि ऋण को बढ़ाने पर जोर देने के लिए बैंकों से कहा गया था कि वे यह सुनिश्चित करें कि प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों का स्तर मार्च, 1985 के अन्त तक 15% और मार्च, 1987 तक 16% हो जाए। इन मानदण्डों की पुनः समीक्षा की गई और बैंकों से कहा गया था कि कृषि क्षेत्र को दिए जाने वाले प्रत्यक्ष वित्त को बढ़ाएं ताकि यह मार्च, 1989 तक उनके कुल ऋणों का 17% [illegible] मार्च, 1990 तक 18% हो जाए। इन लक्ष्यों की तुलना में कृषि (संबद्ध कार्यकलापों सहित) को प्रत्यक्ष वित्त देने में सरकारी क्षेत्र के बैंकों का कार्य निष्पादन निम्नलिखित था:—

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि
मार्च 1989	17%	16.4%
मार्च 1990	18%	16.5%
मार्च 1991	18%	15.1%